लापरवाही • पदों की कमी और अस्थायी भर्ती के चलते अभिभावकों का स्कूलों से मोहभंग

अंग्रेजी माध्यम स्कूल : सरकार ने 3737 स्कूल खोले... ना पर्याप्त पद स्वीकृत किए, ना अलग से कैडर बनाया

विनोद मित्तल | जयपुर

पिछली सरकार ने आनन फानन में हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तो बदल दिया, लेकिन इन स्कूलों में पद स्वीकृत करने के मामले में लापरवाही बरती। महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोलने पर जितने पद स्वीकृत होने थे, उतने पद स्वीकृत ही नहीं किए। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी रही।

इन स्कूलों के लिए अलग से कैडर बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन ना तो कैडर बनाया गया और ना ही इन पदों पर अब स्थायी भर्ती की गई। केवल संविदा के आधार पर भर्ती की गई। प्रदेश में अब तक 3737 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले जा चुके हैं। इन स्कूलों में अलग अलग कैडर के कुल 45212 पद स्वीकृत किए गए। जो जरुरत के मुकाबले बहुत कम है। स्कूलों में तीन प्रमुख शैक्षणिक पद व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक लेवल-1 व 2 के पद भी बहुत कम स्वीकृत किए गए।

एक महात्मा गांधी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक के 6, अध्यापक लेवल वन के 5 और अध्यापक लेवल टू के 2 पद स्वीकृत होने चाहिए। यानी प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक के 22422 पद, लेवल वन के 18685 पद और लेवल टू के 7474 पद स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम यानी वरिष्ठ अध्यापक के 10829, लेवल वन के 9501 और लेवल टू के 5190 पद ही स्वीकृत गए। अन्य कैडर की भी यही स्थिति है। यही कारण है अभिभावकों का भी इन स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को लेकर मोहभंग हो गया है। इस साल 3737 स्कूलों में प्रवेश के लिए महज 85 हजार आवेदन आए। इसके बाद सरकार को एडमिशन की पॉलिसी बदलनी पडी। केवल बाल वाटिका के लिए ही पर्याप्त शिक्षक लगाए गए।

शिक्षकों के इतने पदों का प्रावधान

प्रिंसिपल के 1925 पद, वाइस प्रिंसिपल के 1056 पद, व्याख्याता के 496 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 10829 पद, अध्यापक लेवल वन के 950 अध्यापक लेवल टू के 5170 पद, बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के 877 प पीटीआई प्रथम के 19 पद, पीटीआई द्वितीय के 1071 पद, पीटीआई के 8 पद, प्री प्राइमरी अध्यापक के 2018 पद स्वीकृत किए गए।

गैर शैक्षणिक स्टाफ के इतने पद स्वीकृत

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 111 पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 339 पद, जमादार के 55 पद, जूनियर असिस्टेंट के 1424 पद, लैब असिस्टेंट के 551 पद, लैब बॉय के 140 पद, लाइब्रेरियन प्रथम के 2 पद, लाइब्रेरियन द्वितीय के 143 पद और लाइब्रेरियन तृतीय के 333 पद, सीनियर असिस्टेंट के 606 पद सीनियर लैब असिस्टेंट के 48 पद शामिल है।

स्कूल में पद ऐसे होने थे स्वीकृत

एक महात्मा गांधी स्कूल में प्रिंसिपल क 1, अध्यापक लेवल के 5, अध्याप लेवल टू के 2, वरिष्ठ अध्यापक के 6 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का लाइब्रेरियन का 1, लैब असिस्टेंट का और कंप्यूटर अनुदेशक का 1 पद स्वीकृ होने थे। इसी तरह से वरिष्ठ सहायक क 1, कनिष्ठ सहायक का 1 और सहाय कर्मचारी के 3 पद स्वीकृत किए जाने थे सीनियर स्कूल होने पर वरिष्ठ अध्याप के 3 पद कम करके व्याख्याता के 5 प स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया थ जिन स्कूलों में बाल वाटिका संचालित है वहां प्री प्राइमरी अध्यापक के प्रत्येक स्कूल में 2 पद स्वीकृत होने थे।

ऐतिहासिक फैसले की 4 बड़ी बातें • एससी-एसटी के आरक्षण में सब-कैटेगरी बना सकेंगे राज्य

1. SC-ST में सब-कैटेगरी समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती...

• एससी-एसटी के कोटे में कुछ जातियों की सब-कैटेगरी बनाने से अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं होता है।

2. आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित करना चाहिए, दूसरी हकदार न हो

• एससी/एसटी की पहली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को कोटे का हक न दें।

3. क्रीमीलेयर को इस दायरे से बाहर करने के लिए नीति बनानी चाहिए...

• सरकार को एससी/एसटी श्रेणी के बीच क्रीमीलेयर की पहचान करने व उन्हें दायरे से बाहर करने की नीति भी बनानी चाहिए।

4. राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ या मर्जी से सब-कैटेगरी नहीं बना सकतीं

• अगर राज्य सरकार मर्जी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा से काम करती है तो उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

विरोध शुरू... एनडीए की सहयोगी लोजपा बोली- फैसले पर फिर सोचें

• लोजपा (रामविलास) ने कहा, फैसले पर पुनर्विचार हो, ताकि एससी-एसटी वर्ग में भेदभाव न हो और वे कमजोर न पड़ें।

एससी-एसटी; कोटे में कोटा मंजूर, इसमें भी क्रीमीलेयर को लागू करें: सुप्रीम कोर्ट

पवन कुमार | नई दिल्ली

एससी/एसटी (अनुसूचित जाति/जनजाति) के कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- एससी/एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाकर इस श्रेणी में अति पिछड़ों को अलग कोटा दे सकते हैं। यानी अब राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे एससी/एसटी वर्ग में शामिल सभी समुदायों के लिए आरक्षित कोटे में से जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय करें। वहीं, जस्टिस बीआर गवई ने कहा, क्रीमीलेयर को एससी/एसटी पर भी लागू करें। बता दें कि अभी ओबीसी आरक्षण में सालाना 8 लाख रुपए से ऊपर कमाने वाले लोग क्रीमीलेयर के अंतर्गत आते हैं।

पीठ ने 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र के मामले में दिए फैसले को भी रद्द कर दिया। उसमें कहा गया था कि राज्य सरकार आरक्षित कोटे में सब-कैटेगरी नहीं बना सकते। ताजा फैसला पंजाब के मामले में आया है। दरअसल पंजाब सरकार ने 2006 में कानून बनाया था कि राज्य में एससी/एसटी कैटेगरी के तहत मिलने वाले आरक्षण में से 50% पहली प्राथमिकता के तहत वाल्मीकि और मजहबी सिखों को मिलेगा। इसे पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2010 में इस रद्द कर दिया। इसके खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

– देश-विदेश पेज भी पढ़ें

7 जज...6 फैसले; 6 सहमत, एक असहमत

एससी-एसटी के लोग अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव से सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं होते। अनुच्छेद-14 जाति के उप-वर्गीकरण की मंजूरी देता है।
– सीजेआई डीवाई चंद्रचूड

ईवी चिन्नैया मामले का संदर्भ ही गलत था। विधायी शक्ति के अभाव में राज्यों के पास जातियों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार ही नहीं है।
– जस्टिस बेला त्रिवेदी

भास्कर एक्सपर्ट

एडवोकेट यशस्वी
सीईओ, इंडक्टस लीगल

एससी-एसटी एक समूह नहीं रहेगा, उसमें वर्गों के आधार पर राजनीति शुरू हो जाएगी

1. कोटे में कोटा देने का मतलब क्या है और ये कैसे दिया जाएगा?
अभी एससी के लिए 15% व एसटी के लिए 7.5% आरक्षण है। इस 22.5% के आरक्षण में ही राज्य एससी व एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय कर सकेंगे, जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। किस वर्ग को कितना आरक्षण देना है, इसे तय करने के लिए सरकारें विशेषज्ञ पैनल बना सकती हैं। ये पैनल रिसर्च और डेटा के जरिए बताएगा कि कौन-सा वर्ग आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर कितना पिछड़ा है।

2. कोटा फिक्स कर दिया जाएगा या फिर बार-बार बदलता रहेगा?
डेटा के आधार पर यह कोटा बदलता रहेगा। यह भी देखा जाएगा कि किसी एक वर्ग को 100% आरक्षण न दे दिया जाए। राज्यों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने जिस वर्ग को आरक्षण दिया है, वह अति जरूरतमंद होना चाहिए; उसके पीछे वोट बैंक की मंशा न हो।

3. इसे कब तक लागू किया जाएगा?
यह राज्यों पर निर्भर करेगा। वे जितनी तत्परता दिखाएंगे, उतनी ही जल्दी लागू कर सकते हैं। इसके लिए विस्तृत अध्ययन, हितधारकों से बातचीत और दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

4. फैसले के क्या जोखिम दिखते हैं?
पूरी संभावना है कि एससी-एसटी अब एक समूह नहीं रह जाएगा। उसके भीतर ही अलग-अलग वर्ग खड़े हो जाएंगे और फिर उससे जुड़ी नई तरह की राजनीति शुरू हो सकती है।

5. क्या इस फैसले से ओबीसी और सामान्य श्रेणी पर असर पड़ेगा?
यह फैसला सिर्फ दलित व आदिवासी वर्ग के लिए है। इससे ओबीसी और सामान्य के आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, ये जरूर हो सकता है कि ओबीसी में भी सब-कैटेगरी बनाने की मांग और तेजी से उठने लगे।

6. जातीय जनगणना जरूरी होगी?
चूंकि एससी-एसटी की गणना उपलब्ध है, ऐसे में यह अनिवार्य नहीं होगी।

राजस्थान पर असर

16% आरक्षण एससी के 59 समाजों को, 2 कैटेगरी संभव

जयपुर| सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान में भी एससी आरक्षण का कैटेगराइजेशन संभव है। सरकारी नौकरियों के साथ-साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर भी ये जातियां दावेदारी जता सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रदेश में एससी में 59 समाज लिस्टेड हैं और 16 प्रतिशत आरक्षण राजस्थान में है। ऐसे में कैटेगराइजेशन लागू हुआ तो दो या तीन में आरक्षण बांटा जा सकता है। आरक्षण का प्रतिशत भी बढ़ाकर देने का फार्मूला संभव है। फरवरी 2019 में ओबीसी की पांच जातियों को अलग से 5 प्रतिशत एमबीसी आरक्षण दिया गया था। ये आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में लागू है। ऐसे में एससी कैटेगरी में भी ऐसा ही फॉर्मूला संभव है। विशेषज्ञों की माने तो इसमें प्राथमिकता उन समाजों को मिलेगा जिसे एससी आरक्षण का कम लाभ हुआ है। उधर एससी की अधिक जनसंख्या वाली जगहों पर आरक्षण सीमा बढ़ाने के फार्मूले भी है। शेष | पेज 4

आईबीपीएस: स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती, आवेदन 21 तक

भास्कर संवाददाता | चूरू

बैंक मे अपना करियर बनाने वाले युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन ने देश के 11 सरकारी बैंकों में छह विभाग आईटी अधिकारी, विपणन अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, कानून अधिकारी, मानव संसाधन/कार्मिक अधिकारी में 896 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है।

नेशनल यूथ अवॉर्डी सुधेश पूनिया ने बताया कि भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। एससी, एसटी व पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के अभ्यर्थियों को 175 रुपए आवेदन शुल्क देना पड़ेगा तथा ओबीसी व सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क 850 रुपए तय किया गया है। योग्यता स्नातक तय की गई है। 20 से 28 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट का फायदा भी दिया जाएगा।

यूं कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन : इच्छुक अभ्यर्थी www.ibps.in वेबसाइट पर जाकर खुद के स्तर पर भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को स्कैन सिग्नेचर, फोटो और एक अंडरटेकिंग अपलोड करनी होती है व फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। भर्ती के तहत प्री एग्जाम नवंबर-दिसंबर 2024 में तथा मेन्स एग्जाम 14 दिसंबर 2024 को होगा। अंतिम परिणाम एक अप्रैल 2025 को जारी किया जाएगा।

सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में स्वीकृत बजट पूरा खर्च नहीं

बीकानेर| प्रदेश में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार की कमी के चलते मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में पूरा बजट खर्च नहीं हो रहा है। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को 1000 रुपए प्रतिमाह (दस हजार रुपए वार्षिक) छात्रवृत्ति भुगतान की घोषणा की गई है। बजट घोषणा 2019-20 में अल्पसंख्यक छात्राओं को जिन्होंने 12 वीं कक्षा में 75 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त किए है। उन्हें 500 रुपए प्रतिमाह (अधिकतम 5 हजार रुपए वार्षिक) अतिरिक्त छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है।

क्या है छात्रवृति योजना

नियमित छात्र-छात्राओं को 12वीं में 60% या अधिक अंक पाना और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हों। उन्हें वार्षिक 5 हजार रुपए 5 साल तक छात्रवृत्ति देय है। यूजी प्रथम वर्ष में वरीयता के आधार पर एक लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। यूजी प्रथम वर्ष के बाद अग्रिम कक्षाओं में निर्धारित पात्रता पूर्ण करने पर छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है।

युवा-शिक्षा-अवसर

पीजी प्रीवियस • पिछले साल 26 जुलाई से शुरू हुए ऑनलाइन आवेदन, 15 सितंबर से लगीं कक्षाएं

पीजी की सभी फैकल्टी में सेमेस्टर प्रणाली लागू, दिसंबर में परीक्षा, प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं

एजुकेशन रिपोर्टर | बीकानेर

पीजी प्रीवियस में इस बार एक्स्ट्रा क्लास लगाकर विद्यार्थियों का कोर्स पूरा कराना होगा। जुलाई का पूरा महीना बीत जाने के बाद भी सरकारी कॉलेजों में पीजी प्रीवियस के प्रवेश शुरू नहीं हुए हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने नए शिक्षा सत्र 2024 - 25 से पीजी प्रीवियस की सभी फैकल्टी में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी है। सेमेस्टर प्रणाली के तहत विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए अब साल में दो परीक्षाएं देनी होंगी।

पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर में प्रस्तावित हैं। लेकिन कॉलेज आयुक्तालय की ओर से अभी तक पीजी प्रीवियस में प्रवेश का शेड्यूल घोषित नहीं किया है। पिछले साल स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से शुरू कर दिए गए थे। जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई। पीजी प्रीवियस की कक्षाएं 15 सितंबर से शुरू हुईं। वर्तमान शिक्षा सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं होने से स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध का सेशन प्रभावित होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि कॉलेज आयुक्तालय ने सभी विश्वविद्यालयों से स्नातक फाइनल ईयर के परीक्षा परिणाम की जानकारी मांगी है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक फाइनल ईयर के सभी परिणाम घोषित किया जा चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक पीजी के प्रवेश का शेड्यूल घोषित हो सकता है।

स्नातक फाइनल ईयर के सभी रिजल्ट घोषित

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक अंतिम वर्ष के सभी परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुके हैं। विश्वविद्यालय की ओर से अब पूरक परीक्षा की तैयारी की जा रही है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि स्नातक की पूरक परीक्षाएं अगले माह सितंबर में आयोजित की जाएगी।

डूंगर कॉलेज में 1160 और एमएस कॉलेज में 360 सीटें निर्धारित

डूंगर कॉलेज के पीजी प्रीवियस में 1160 विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा। यहां एमए में 750, एम कॉम में 180 और एमएससी में 230 सीट निर्धारित है। वहीं एमएस कॉलेज में तीनों संकायों में 360 सीट निर्धारित हैं। जिसमें एमए की 270, एम कॉम में 60, और एमएससी में 30 पर छात्राओं का एडमिशन होगा।

विश्वविद्यालय की ओर से पीजी प्रीवियस के सभी संकाय में इस साल से सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। जिसके तहत साल में दो बार परीक्षा आयोजित होगी। 90 दिन का सेशन पूरा होने के बाद प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी। प्रो. राजाराम चोयल, परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

इंग्लिश स्कूलों में 74 प्रतिशत सहायक कर्मचारियों के पद खाली

बीकानेर | राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सहायक कर्मचारी के 74 फीसदी से अधिक पद रिक्त हैं। प्रदेश में वर्तमान में 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल संचालित किया जा रहे हैं जिनमें सहायक कर्मचारी के 2937 पद स्वीकृत हैं। इनमें 2185 पद खाली हैं। राज्य में 1010 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। इन कक्षाओं के लिए प्रति स्कूल प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व सफाई कर्मी की सेवाएं लेने का प्रावधान है। रिक्त पदों की यह स्थिति केवल अंग्रेजी स्कूलों में ही नहीं है। हिंदी मीडियम स्कूलों में भी सहायक कर्मचारी के 22 हजार से अधिक पद खाली हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ोतरी के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार उदासीन है। राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने रिक्त पदों को भरने की मांग की है। विदित रहे कि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में टीचर्स के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन ले लिए हैं। जल्द ही इन पदों को भरने के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन सहायक कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने के लिए अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सहायक कर्मचारियों के पदों को केवल अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर भरा जा रहा है।

सीबीएसई : परीक्षा के 24 दिन बाद ही सीटेट का परिणाम जारी

बीकानेर | सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2024 का परिणाम परीक्षा के 24 दिन बाद ही कर दिया। प्रथम लेवल का परिणाम 18.73 और दूसरे लेवल का परिणाम 16.99 प्रतिशत रहा। प्रथम लेवल में 1.74 फीसदी स्टूडेंट्स अधिक पास हुए हैं। सीबीएसई ने 7 जुलाई को सीटेट अजमेर सहित देशभर के 135 शहरों में हुई। यह परीक्षा 20 भाषाओं में हुई थी। लेवल वन व लेवल सेकंड के लिए 25 लाख 30 हजार 65 परीक्षार्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से लेवल प्रथम के लिए 8 लाख 30 हजार 242 और लेवल सेकंड के लिए 16 लाख 99 हजार 823 परीक्षार्थी थे। इनमें से 20 लाख 86 हजार 39 ने परीक्षा दी। 4 लाख 44 हजार 26 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने आवेदन करने के बावजूद परीक्षा नहीं दी। परीक्षा देने वालों में लेवल वन के लिए 6 लाख 78 हजार 707 और लेवल सेकंड के लिए 14 लाख 7 हजार 332 अभ्यर्थी शामिल रहे। अभ्यर्थी सीटेट की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर अपलोड कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

शिक्षक भर्ती - 2022 : दो विषयों के 161 सेकंड ग्रेड शिक्षकों को मंडल आवंटित

एजुकेशन रिपोर्टर | बीकानेर

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा - 2022 में अंग्रेजी और उर्दू विषय के वेटिंग सूची से चयनित 161 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मंडल आवंटन किए हैं। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संभाग स्तर पर की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को इस संबंध में निर्देश भी दे दिए हैं। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 5 अगस्त को होगी। इनके नियुक्ति आदेश काउंसलिंग के बाद उसी दिन जारी किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों में 154 अंग्रेजी के और 7 उर्दू विषय के हैं।

संस्कृत कॉलेज में प्रथम वर्ष के आवेदन अब 16 तक

एजुकेशन रिपोर्टर | बीकानेर

श्री गंगा सादुल राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्री बीए प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश के ऑफलाइन आवेदन अब 16 अगस्त तक लिए जाएंगे। शिक्षा सत्र 2024- 25 के लिए प्रवेश के आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी कर दी गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ .महावीर प्रसाद सारस्वत ने बताया कि प्रथम अंतरिम प्रवेश सूची का प्रकाशन अब 20 अगस्त को किया जाएगा। 27 अगस्त को अंतरिम प्रवेश सूची के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि और 29 अगस्त को प्रवेशित सूची प्रकाशित होगी। सीटें रिक्त रहने पर द्वितीय वरीयता सूची दो सितंबर को घोषित की जाएंगी। द्वितीय वरीयता सूची के छात्रों द्वारा फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर निर्धारित की गई है।

महिला पर्यवेक्षक भर्ती : 60 पद बढ़ेंगे

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 22 जून को आयोजित की गई पर्यवेक्षक महिला (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) भर्ती में 60 पद बढ़ सकते हैं। इसके बाद इस भर्ती में पदों की संख्या 262 हो जाएगी। इससे पहले यह भर्ती 202 के लिए प्रारंभ की गई थी। पद बढ़ने का अधिकृत सूचना मिलने के बाद ही अब इस भर्ती का परिणाम जारी हो सकेगा। अभ्यर्थी इस भर्ती के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पद बढ़ने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए इस साल फरवरी-मार्च में आवेदन लिए गए थे। परीक्षा 22 जून को 7 शहरों में आयोजित की गई थी। इस भर्ती में 14977 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

भारतीय पशुपालन निगम : रिक्त पदों पर भर्ती करेगा

बीकानेर | भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा रिक्त चल रहे पदों को पुनः भरा जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग, कार्यालय सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रशिक्षण प्रभारी, प्रशिक्षण समन्वय प्रशिक्षण सहायक एवं पशु सेवक के शेष रहे 9173 पदों हेतु अगस्त एवं नवंबर में आवेदन मांगे जाएंगे।

कल मिलेंगे सेकंड सेमेस्टर परीक्षा के प्रवेश पत्र

बीकानेर | बीकानेर संभाग के कॉलेजों में पढ़ने वाले स्नातक प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों की सेकंड सेमेस्टर परीक्षाएं 8 अगस्त से शुरू होंगी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राजाराम चोयल ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले संभाग के 1.10 लाख अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 3 अगस्त को जारी कर दिए जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 सितंबर तक चलेंगी।

भास्कर Analysis • राजस्थान बोर्ड के सीबीएसई पैटर्न पर आते ही कॉलेजों में दिखा प्रवेश का संघर्ष

अब तक का सबसे हाई कॉम्पिटिशन, 99% पर पहला प्रवेश...84% वाले भी वेटिंग में

भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा

12वीं बोर्ड रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में जाने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ दिया जाए तो एकेडमिक कॉलेज में पास कोर्स में एडमिशन लेना पहला विकल्प माना जाता रहा है। राजकीय महाविद्यालयों में जहां 45-50 प्रतिशत लाने वाले स्टूडेंट्स को आसानी से एडमिशन मिल जाया करता था, वहीं अब इन प्रतिशत वाले स्टूडेंट्स वेटिंग में भी नहीं आ पा रहे हैं।

2019 से 2024 तक छह वर्षों का एडमिशन स्कोर इतना बढ़ गया है कि 99 प्रतिशत तक पहुंच गया है। एमएलवी कॉलेज में बीए पार्ट 1 में पहले नंबर पर आने वाले स्टूडेंट को 99 प्रतिशत मिले हैं। इतना स्कोर करने के बाद पहली मेरिट लिस्ट की कटऑफ 85.6 प्रतिशत (गर्ल्स) तक वालों को ही प्रवेश मिल सकता है। 85% से कम वाले फिलहाल वेटिंग में हैं।

बीएससी बायोलॉजी और मैथ्स में स्थितियां जरूर उलट-पलट गई है। 2019 में जहां मैथ्स की कटऑफ 83.6 प्रतिशत थी, वहीं 2024 में 79.6% कॉमन) कट ऑफ रही। मैथ्स में 2019 में 65.4% वेटिंग प्रतिशत भी 49.4% तक रह गया। जबकि बायोलॉजी में 2019 में 72.4% थी जो 2024 में बढ़कर 83.4% कॉमन) हो गई है और वेटिंग 64.2% से 67.2 प्रतिशत हो गया है। इसका कारण है कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक या अन्य तकनीकी कोर्सेज में जाना पसंद करते हैं।

वहीं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए नीट की सीमित सीटों के कारण बीएससी कोर्स करना ही विकल्प है।

पेपर पैटर्न बदलने से बढ़ा है 12वीं का स्कोर, कॉलेज में प्रवेश की कटऑफ भी इसीलिए बढ़ी

इस बार आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही संकायों के रिजल्ट में स्टूडेंट्स को अच्छे अंक मिलने के पीछे दो मूल कारण रहे हैं। पहला कारण तो यह रहा है कि पेपर पैटर्न में बदलाव लाया गया है। प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार एक अंक के प्रश्नों यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न भी पूछे गए। सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या और शब्द सीमा भी घटा दी गई, इस बदलाव ने भी हाई स्कोर करने में अहम भूमिका निभाई है। सब्जेक्टिव प्रश्नों में पहले कम अंक ही मिलते थे, लेकिन इसमें भी अब पूरे मार्क्स आने की संभावना बढ़ गई है। पेपर में 5 प्रतिशत कठिन प्रश्न तो होते हैं, इन्हीं की वजह से सामान्य और विशेष स्टूडेंट्स में अंतर दिखाई देता है। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड ने भी इस बार से सीबीएसई बोर्ड से प्रतिस्पर्धा करते हुए पेपर पैटर्न सीबीएसई जैसा ही रखने की शुरुआत की। इसकी वजह थी कि हर बार कॉलेज की मेरिट लिस्ट में सीबीएसई स्टूडेंट्स के हाई स्कोर होते थे और राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को तुलनात्मक कम प्रतिशत मिलते थे। इस कारण कॉलेज में सीबीएसई स्टूडेंट्स का सीटों पर कब्जा हो जाता था और राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स पीछे रह जाते थे। इसे देखते हुए भी राजस्थान बोर्ड ने पेपर पैटर्न में बदलाव किया और स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया। अब सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड दोनों के ही स्टूडेंट्स बराबरी पर हैं। एक कारण और है स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर पहले से अधिक गंभीर हो गए हैं। एक-एक नंबर के लिए वे संघर्ष करते हैं और वर्तमान प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

-कश्मीर भट्ट, प्रोफेसर ज्योग्राफी, एमएलवी कॉलेज

इस सत्र से 30% लड़कियों की सीट रिजर्व करने से एमएलवी में सभी कोर्स में 50% से अधिक लड़कियां

कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने इस सत्र से 30% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया है। इस वजह से इस वर्ष मेरिट लिस्ट में कॉमन और गर्ल्स की कटऑफ अलग-अलग जारी की गई है। सभी विषयों में लड़कियों की अच्छी स्कोरिंग रहने के कारण कटऑफ भी सर्वाधिक बायो में 87% और आर्ट्स में 85.6% रही है। इतना ही नहीं 30% सीट रिजर्व होने से संकाय की मेरिट लिस्ट में लड़कियों को सीट मिल ही गई, साथ ही कॉमन में भी लड़कों से अच्छी स्कोरिंग करने के कारण 50 फीसदी सीटों पर कब्जा जमा लिया है। एमएलवी में बीए पार्ट 1 में सामान्य की 504 सीटों पर 251 लड़कियों ने प्रवेश पा लिया है।

लापरवाही • पदों की कमी और अस्थायी भर्ती के चलते अभिभावकों का स्कूलों से मोहभंग

अंग्रेजी माध्यम स्कूल : सरकार ने 3737 स्कूल खोले... ना पर्याप्त पद स्वीकृत किए, ना अलग से कैडर बनाया

विनोद मित्तल | जयपुर

पिछली सरकार ने आनन फानन में हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तो बदल दिया, लेकिन इन स्कूलों में पद स्वीकृत करने के मामले में लापरवाही बरती। महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोलने पर जितने पद स्वीकृत होने थे, उतने पद स्वीकृत ही नहीं किए। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी रही।

इन स्कूलों के लिए अलग से कैडर बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन ना तो कैडर बनाया गया और ना ही इन पदों पर अब स्थायी भर्ती की गई। केवल संविदा के आधार पर भर्ती की गई। प्रदेश में अब तक 3737 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले जा चुके हैं। इन स्कूलों में अलग अलग कैडर के कुल 45212 पद स्वीकृत किए गए। जो जरुरत के मुकाबले बहुत कम है। स्कूलों में तीन प्रमुख शैक्षणिक पद व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक लेवल-1 व 2 के पद भी बहुत कम स्वीकृत किए गए।

एक महात्मा गांधी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक के 6, अध्यापक लेवल वन के 5 और अध्यापक लेवल टू के 2 पद स्वीकृत होने चाहिए। यानी प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक के 22422 पद, लेवल वन के 18685 पद और लेवल टू के 7474 पद स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम यानी वरिष्ठ अध्यापक के 10829, लेवल वन के 9501 और लेवल टू के 5190 पद ही स्वीकृत गए। अन्य कैडर की भी यही स्थिति है। यही कारण है अभिभावकों का भी इन स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को लेकर मोहभंग हो गया है। इस साल 3737 स्कूलों में प्रवेश के लिए महज 85 हजार आवेदन आए। इसके बाद सरकार को एडमिशन की पॉलिसी बदलनी पडी। केवल बाल वाटिका के लिए ही पर्याप्त शिक्षक लगाए गए।

शिक्षकों के इतने पदों का प्रावधान

प्रिंसिपल के 1925 पद, वाइस प्रिंसिपल के 1056 पद, व्याख्याता के 4965 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 10829 पद, अध्यापक लेवल वन के 9501, अध्यापक लेवल टू के 5170 पद, बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के 877 पद, पीटीआई प्रथम के 19 पद, पीटीआई द्वितीय के 1071 पद, पीटीआई के 851 पद, प्री प्राइमरी अध्यापक के 2018 पद स्वीकृत किए गए।

गैर शैक्षणिक स्टाफ के इतने पद स्वीकृत

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 111 पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 339 पद, जमादार के 55 पद, जूनियर असिस्टेंट के 1424 पद, लैब असिस्टेंट के 551 पद, लैब बॉय के 140 पद, लाइब्रेरियन प्रथम के 2 पद, लाइब्रेरियन द्वितीय के 143 पद और लाइब्रेरियन तृतीय के 333 पद, सीनियर असिस्टेंट के 606 पद सीनियर लैब असिस्टेंट के 48 पद शामिल है।

स्कूल में पद ऐसे होने थे स्वीकृत

एक महात्मा गांधी स्कूल में प्रिंसिपल का 1, अध्यापक लेवल के 5, अध्यापक लेवल टू के 2, वरिष्ठ अध्यापक के 6, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का 1, लाइब्रेरियन का 1, लैब असिस्टेंट का 1 और कंप्यूटर अनुदेशक का 1 पद स्वीकृत होने थे। इसी तरह से वरिष्ठ सहायक का 1, कनिष्ठ सहायक का 1 और सहायक कर्मचारी के 3 पद स्वीकृत किए जाने थे। सीनियर स्कूल होने पर वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद कम करके व्याख्याता के 5 पद स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया था। जिन स्कूलों में बाल वाटिका संचालित है, वहां प्री प्राइमरी अध्यापक के प्रत्येक स्कूल में 2 पद स्वीकृत होने थे।

एमडीएसयू पीजी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग

जयपुर| एमडीएस यूनिवर्सिटी के गणित और बॉटनी विभाग में पीजी प्रीवियस में प्रवेश के लिए एक दिवसीय काउंसलिंग गुरुवार को हुई। काउंसलिंग के बाद भी सभी सीटें नहीं भरीं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स 75 फीसदी हाजिरी जरूरी होने के फार्म को देखकर वापस लौट गए। काउंसलिंग से बॉटनी की 20 और गणित की 40 सीटों पर प्रवेश दिया जाना था। बॉटनी में 33 और गणित में प्रवेश के लिए 30 विद्यार्थियों को बुलाया था। बॉटनी के लिए 20 विद्यार्थी ही पहुंचे। मैथ्स के लिए 22 विद्यार्थी आए। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पारीक के मुताबिक मैथ्स 7 सीटों पर वहीं बॉटनी में 11 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ है। दोनों विभागों में जो सीटें खाली रह गई हैं उन पर प्रवेश के लिए एक बार फिर एडमिशन पोर्टल खोला जाएगा।

गणित की भाषा हिंदी और सिंधी में भी समझ सकेंगे छात्र

जयपुर| अब गणित के कठिन शब्दों के बदले हिंदी के आसान शब्दों को ईजाद किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एसपीसीजीसीए के शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग शुरू की गई है। यह सब प्रक्रिया राजभाषा आयोग के निर्देश पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की देखरेख में किया जाएगा। गणित को मूलभूत शब्दावली योजना के तहत आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन यह प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 7 साल पहले राजनीति विज्ञान के लिए ऐसी ही शब्दावली ईजाद की गई थी। राजभाषा आयोग नई शब्दावली के आधार पर गणित की डिक्शनरी तैयार कराएगा। ताकि विद्यार्थियों के साथ ही आम लोग भी गणित की भाषा को आसान शब्दों में समझ सकें। इसके अलावा एसपीसी जीसीए के ही 6 शिक्षकों को सिंधी भाषा की शब्दावली गढ़ने के लिए चुना है। गुरुवार को पहली बैठक एसपीसी जीसीए में की गई।

महिला पर्यवेक्षक भर्ती : 60 पद बढ़ेंगे

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 22 जून को आयोजित की गई पर्यवेक्षक महिला (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) भर्ती में 60 पद बढ़ सकते हैं। इसके बाद इस भर्ती में पदों की संख्या 262 हो जाएगी। इससे पहले यह भर्ती 202 के लिए प्रारंभ की गई थी। पद बढ़ने का अधिकृत सूचना मिलने के बाद ही अब इस भर्ती का परिणाम जारी हो सकेगा। अभ्यर्थी इस भर्ती के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पद बढ़ने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए इस साल फरवरी-मार्च में आवेदन लिए गए थे। परीक्षा 22 जून को 7 शहरों में आयोजित की गई थी। इस भर्ती में 14977 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

भारतीय पशुपालन निगम : रिक्त पदों पर भर्ती करेगा

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा रिक्त चल रहे पदों को पुनः भरा जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग, कार्यालय सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रशिक्षण प्रभारी, प्रशिक्षण समन्वय प्रशिक्षण सहायक एवं पशु सेवक के शेष रहे 9173 पदों हेतु अगस्त एवं नवंबर में आवेदन मांगे जाएंगे।

फिजिक्स वाला की मार्केटिंग इंटर्नशिप

फिजिक्स वाला की ओर से मार्केटिंग इंटर्न के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह एक पूर्णकालिक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसकी अवधि दो माह निर्धारित की गई है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत छात्रों को सप्ताह में पांच दिन काम करने का मौका मिलेगा। छात्रों में कंटेंट राइटिंग, डिजाइन थिंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एमएस-एक्सेल, एमएस-ऑफिस व सोशल मीडिया मार्केटिंग का कौशल होना चाहिए। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत विज्ञापन, सोशल मीडिया पोस्ट और वेबसाइट कंटेंट सहित आकर्षक मार्केटिंग कंटेंट विकसित करने के लिए डिजाइन और कंटेंट टीम के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। चयनितों को प्रतिमाह 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। मार्केटिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम में आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त, 2024 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक https://tinyurl.com/muj8a5h8 पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन आमंत्रित

शेफलर सोशल इनोवेटर फेलोशिप

शेफलर इंडिया की ओर से शेफलर इंडिया सोशल इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह फेलोशिप प्रोग्राम ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए है, जिनके कार्य समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। भारत के नागरिक फेलोशिप प्रोग्राम में आवेदन करने के पात्र हैं। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। फेलोशिप के तहत 10 विजेताओं में से प्रत्येक को 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2024 निर्धारित की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक वेबसाइट schaefflerindia-socialinnovators.com पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

फेलोशिप प्रोग्राम

छात्रसंघ चुनावी फंड को वेतन व पेंशन में खपाया, छात्र लाइब्रेरी में किताबों और सुविधाओं को तरस रहे

जेएनवीयू: 3 सत्रों में छात्रसंघ चुनाव के 82 लाख वसूले, स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए नहीं किए खर्च

125 रुपए प्रति छात्र वसूली, हर साल 27 लाख छात्रसंघ फंड

जोधपुर| जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पिछले चार सत्रों में से तीन सत्रों में छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाए गए। वहीं इस सत्र में भी अब तक छात्रसंघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति कायम है। विवि ने तीन सत्रों में छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के बावजूद स्टूडेंट्स से फीस में छात्रसंघ चुनावी फंड के मद में कुल 82 लाख रुपए से अधिक राशि की वसूली की थी।

सूत्रों की मानें तो विवि प्रशासन ने 82 लाख रुपए को वेतन व पेंशन मदों में ही खपा दिया, जबकि स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में किताबों और अन्य सुविधाओं को तरसते रह गए। हैरत की बात यह है कि छात्रसंघ फंड की राशि के स्टूडेंट्स हित में उपयोग नहीं होने के बावजूद भी छात्र संगठनों ने चुप्पी बनाए रखी है।

जेएनवीयू के नियमों के तहत रेगुलर स्टूडेंट्स की फीस के मदों में से प्रति छात्र 125 रुपए छात्रसंघ चुनाव के मद में वसूले जाते हैं। इसमें 50 रुपए स्टूडेंट्स यूनियन फीस, 50 रुपए फैकल्टी या कॉलेज स्टूडेंट यूनियन फीस और 25 रुपए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन फीस के लिए जाते हैं। ऐसे में विवि के यूजी व पीजी के करीब 22 हजार नियमित स्टूडेंट्स से हर साल करीब 27 लाख 50 हजार रुपए की वसूली की जाती है। इस फंड को छात्रसंघ के चुनाव के बाद अध्यक्ष को ट्रांसफर किया जाता है। छात्रसंघ पदाधिकारियों द्वारा फंड को छात्र हितों व आयोजनों में ही खर्च करना होता है।

फंड का उपयोग छात्र हित में हो

छात्रसंघ चुनाव के फंड का उपयोग छात्रों के हित में किया जाना चाहिए। छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर एकत्रित फंड से किताबें खरीदने, छात्रों की सुविधाओं के लिए खर्च का प्लान बनाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार से भी मांग की जाएगी।
- रविंद्रसिंह भाटी, विधायक शिव व पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष जेएनवीयू

तीन सत्र से चुनाव बंद, 82 लाख का फंड एकत्रित

जेएनवीयू में कोरोना काल में वर्ष 2020 व 2021 में लगातार दो साल छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाए गए। इसके बाद वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के कारण से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए। ऐसे में पिछले चार सालों में से तीन साल छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए, मगर विवि प्रशासन ने छात्रसंघ चुनाव के मद में लगातार वसूली जारी रखी। ऐसे में तीन सत्रों में करीब 82 लाख 50 हजार रुपयों की वसूली की गई। इस राशि का छात्र हित में कोई उपयोग नहीं किया गया। इस साल भी अब तक छात्रसंघ चुनाव की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इसके बावजूद यूजी व पीजी छात्रों से फीस मद में कुल करीब 26 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं।

पूर्व वीसी ने किताबें खरीदी थीं, अब फंड छात्रों से दूर

विवि में पूर्व कुलपति स्व. प्रो. नवीन माथुर के कार्यकाल में छात्रसंघ चुनाव के फंड से लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने की पहल की गई थी। इसके बाद कई सालों तक छात्रसंघ चुनाव पर रोक रही थी, मगर विवि की फीस में फिर भी चुनाव के फंड में वसूली होती रही। इस फंड का छात्रों के हित में उपयोग नहीं हो पाया। हाल ही के तीन सत्रों में चुनाव नहीं होने के बाद भी छात्रसंघ चुनावी फंड को छात्रों के हित में खर्च नहीं किया जा रहा है।

प्री.डीएलएड : कॉलेज आवंटन 4 को, रिपोर्टिंग 12 तक

जोधपुर| प्रदेश में 376 डीएलएड कॉलेजों की करीब 26 हजार सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित प्री डीएलएड प्रक्रिया के तहत 4 अगस्त को कॉलेज अलॉटमेंट सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। कॉलेज आवंटन के बाद 4 से 11 अगस्त तक फीस जमा करवानी होगी। प्री डीएलएड के को-ऑर्डिनेटर डॉ. रवि गुप्ता ने बताया कि 4 अगस्त को कॉलेज आवंटन के बाद 4 से 11 अगस्त तक फीस जमा करवानी होगी। 5 से 12 अगस्त तक आवंटित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन करवाने के बाद में रिपोर्टिंग करनी होगी। पहले चरण में कॉलेज आवंटन के बाद अभ्यर्थी कॉलेज में बदलाव के लिए अपवर्ड मूवमेंट प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए पहले अभ्यर्थियों को पहले चरण में आवंटित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन व फीस अदायगी करके रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। इसके बाद 14 से 16 अगस्त तक अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करना होगा। अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज आवंटन 19 अगस्त को होगा।

कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करने पर राशि लौटाएंगे

डॉ. गुप्ता ने बताया कि कॉलेज आवंटन से वंचित अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क 3000 रुपए में से 100 रुपए काटकर 2900 रुपए लौटा दिए जाएंगे। संस्था आवंटन के पश्चात नॉन रिपोर्टिंग अभ्यर्थियों के 500 रुपए काटकर 2500 रुपए 45 दिवस में लौटा दिए जाएंगे।

पुरालेखपाल व अन्य पदों का एग्जाम 3 से, 7041 अभ्यर्थी होंगे शामिल

जोधपुर| राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कला साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के 5 विभिन्न पदों की परीक्षाओं का आयोजन 3 से 5 अगस्त तक अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। परीक्षाओं में ओएमआर उत्तर-पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इन परीक्षाओं के लिए 7041 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं।

परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 3 अगस्त को पुरालेखपाल के 3 पदों के लिए परीक्षा 7 केंद्रों पर सुबह 10 से 12.30 बजे तक एवं सहायक पुरालेखपाल के 2 पदों के लिए परीक्षा 8 केंद्रों पर दोपहर 3 से 5.30 बजे तक होगी। 4 अगस्त को शोध अध्येता के 1 पद के लिए परीक्षा 4 केंद्रों पर सुबह 10 से 12.30 बजे तक एवं शोध अधिकारी के 1 पद के लिए परीक्षा दोपहर 3 से 5.30 बजे तक 6 केंद्रों पर होगी। 5 अगस्त को रसायनज्ञ के 1 पद के लिए परीक्षा सुबह 10 से 12.30 बजे तक 5 केंद्रों पर होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा।

सीबीएसई : परीक्षा के 24 दिन बाद ही सीटेट का परिणाम जारी

जयपुर| सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2024 का परिणाम परीक्षा के 24 दिन बाद ही कर दिया। प्रथम लेवल का परिणाम 18.73 और दूसरे लेवल का परिणाम 16.99 प्रतिशत रहा। प्रथम लेवल में 1.74 फीसदी स्टूडेंट्स अधिक पास हुए हैं। सीबीएसई ने 7 जुलाई को सीटेट अजमेर सहित देशभर के 135 शहरों में हुई। यह परीक्षा 20 भाषाओं में हुई थी। लेवल वन व लेवल सेकंड के लिए 25 लाख 30 हजार 65 परीक्षार्थियों ने आवेदन किए थे। इनमें से लेवल प्रथम के लिए 8 लाख 30 हजार 242 और लेवल सेकंड के लिए 16 लाख 99 हजार 823 परीक्षार्थी थे। इनमें से 20 लाख 86 हजार 39 ने परीक्षा दी। 4 लाख 44 हजार 26 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने आवेदन करने के बावजूद परीक्षा नहीं दी। परीक्षा देने वालों में लेवल वन के लिए 6 लाख 78 हजार 707 और लेवल सेकंड के लिए 14 लाख 7 हजार 332 अभ्यर्थी शामिल रहे। अभ्यर्थी सीटेट की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर अपलोड कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

महिला पर्यवेक्षक भर्ती : 60 पद बढ़ेंगे

जयपुर| राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 22 जून को आयोजित की गई पर्यवेक्षक महिला (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) भर्ती में 60 पद बढ़ सकते हैं। इसके बाद इस भर्ती में पदों की संख्या 262 हो जाएगी। इससे पहले यह भर्ती 202 के लिए प्रारंभ की गई थी। पद बढ़ने का अधिकृत सूचना मिलने के बाद ही अब इस भर्ती का परिणाम जारी हो सकेगा। अभ्यर्थी इस भर्ती के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

गणित की भाषा हिंदी और सिंधी में भी समझ सकेंगे छात्र

जयपुर| अब गणित के कठिन शब्दों के बदले हिंदी के आसान शब्दों को ईजाद किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एसपीसीजीसीए के शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग शुरू की गई है। यह सब प्रक्रिया राजभाषा आयोग के निर्देश पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की देखरेख में किया जाएगा। गणित को मूलभूत शब्दावली योजना के तहत आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन यह प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 7 साल पहले राजनीति विज्ञान के लिए ऐसी ही शब्दावली ईजाद की गई थी। राजभाषा आयोग नई शब्दावली के आधार पर गणित की डिक्शनरी तैयार कराएगा। ताकि विद्यार्थियों के साथ ही आम लोग भी गणित की भाषा को आसान शब्दों में समझ सकें। इसके अलावा एसपीसी जीसीए के ही 6 शिक्षकों को सिंधी भाषा की शब्दावली गढ़ने के लिए चुना है।

कॉलेज में 75% से कम अटेंडेंस पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी

जोधपुर| कॉलेजों के नियमित स्टूडेंट्स के 75 प्रतिशत से कम अटेंडेंस होने पर छात्रवृत्ति सहित कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। साथ ही सेमेस्टर सिस्टम में इंटरनल असेसमेंट व मिड टर्म से भी स्टूडेंट्स को वंचित कर दिया जाएगा। कॉलेज आयुक्तालय ने कॉलेजों को निर्देश जारी किए हैं। आयुक्तालय के निर्देशों से स्टूडेंट्स की नियमित रूप से अटेंडेंट लेनी होगी। इसमें निर्धारित कार्य दिवसों में 75 प्रतिशत अटेंडेंट नहीं होने पर स्टूडेंट्स को एग्जाम से वंचित किया ही जाएगा।

इन सुविधाओं से रहेंगे वंचित: 75 प्रतिशत से कम अटेंडेंस होने पर छात्राओं को कालीबाई भील स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना से वंचित रहना पड़ सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बीएड) संबल योजना, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

एडमिशन फीस 6 तक, 8 से नए प्रवेश

सरकारी कॉलेजों में दस्तावेज सत्यापन व ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 6 अगस्त कर दी गई थी। संशोधित ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी 6 अगस्त तक दस्तावेज सत्यापन व ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकेंगे। ऑनलाइन कैटेगरी वाइज नए प्रवेश के लिए भी 8 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।

लापरवाही • पदों की कमी और अस्थायी भर्ती के चलते अभिभावकों का स्कूलों से मोहभंग

अंग्रेजी माध्यम स्कूल : सरकार ने 3737 स्कूल खोले... ना पर्याप्त पद स्वीकृत किए, ना अलग से कैडर बनाया

विनोद मित्तल | जयपुर

पिछली सरकार ने आनन फानन में हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तो बदल दिया, लेकिन इन स्कूलों में पद स्वीकृत करने के मामले में लापरवाही बरती। महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोलने पर जितने पद स्वीकृत होने थे, उतने पद स्वीकृत ही नहीं किए। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी रही।

इन स्कूलों के लिए अलग से कैडर बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन ना तो कैडर बनाया गया और ना ही इन पदों पर अब स्थायी भर्ती की गई। केवल संविदा के आधार पर भर्ती की गई। प्रदेश में अब तक 3737 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले जा चुके हैं। इन स्कूलों में अलग अलग कैडर के कुल 45212 पद स्वीकृत किए गए। जो जरुरत के मुकाबले बहुत कम है। स्कूलों में तीन प्रमुख शैक्षणिक पद व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक लेवल-1 व 2 के पद भी बहुत कम स्वीकृत किए गए।

एक महात्मा गांधी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक के 6, अध्यापक लेवल वन के 5 और अध्यापक लेवल टू के 2 पद स्वीकृत होने चाहिए। यानी प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक के 22422 पद, लेवल वन के 18685 पद और लेवल टू के 7474 पद स्वीकृत होने चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम यानी वरिष्ठ अध्यापक के 10829, लेवल वन के 9501 और लेवल टू के 5190 पद ही स्वीकृत गए। अन्य कैडर की भी यही स्थिति है। यही कारण है अभिभावकों का भी इन स्कूलों में बच्चों के प्रवेश को लेकर मोहभंग हो गया है। इस साल 3737 स्कूलों में प्रवेश के लिए महज 85 हजार आवेदन आए। इसके बाद सरकार को एडमिशन की पॉलिसी बदलनी पडी। केवल बाल वाटिका के लिए ही पर्याप्त शिक्षक लगाए गए।

शिक्षकों के इतने पदों का प्रावधान

प्रिंसिपल के 1925 पद, वाइस प्रिंसिपल के 1056 पद, व्याख्याता के 4965 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 10829 पद, अध्यापक लेवल वन के 9501, अध्यापक लेवल टू के 5170 पद, बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के 877 पद, पीटीआई प्रथम के 19 पद, पीटीआई द्वितीय के 1071 पद, पीटीआई के 851 पद, प्री प्राइमरी अध्यापक के 2018 पद स्वीकृत किए गए।

गैर शैक्षणिक स्टाफ के इतने पद स्वीकृत

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 111 पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 339 पद, जमादार के 55 पद, जूनियर असिस्टेंट के 1424 पद, लैब असिस्टेंट के 551 पद, लैब बॉय के 140 पद, लाइब्रेरियन प्रथम के 2 पद, लाइब्रेरियन द्वितीय के 143 पद और लाइब्रेरियन तृतीय के 333 पद, सीनियर असिस्टेंट के 606 पद सीनियर लैब असिस्टेंट के 48 पद शामिल है।

स्कूल में पद ऐसे होने थे स्वीकृत

एक महात्मा गांधी स्कूल में प्रिंसिपल का 1, अध्यापक लेवल के 5, अध्यापक लेवल टू के 2, वरिष्ठ अध्यापक के 6, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का 1, लाइब्रेरियन का 1, लैब असिस्टेंट का 1 और कंप्यूटर अनुदेशक का 1 पद स्वीकृत होने थे। इसी तरह से वरिष्ठ सहायक का 1, कनिष्ठ सहायक का 1 और सहायक कर्मचारी के 3 पद स्वीकृत किए जाने थे। सीनियर स्कूल होने पर वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद कम करके व्याख्याता के 5 पद स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया था। जिन स्कूलों में बाल वाटिका संचालित है, वहां प्री प्राइमरी अध्यापक के प्रत्येक स्कूल में 2 पद स्वीकृत होने थे।

एमडीएसयू पीजी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग

जयपुर| एमडीएस यूनिवर्सिटी के गणित और बॉटनी विभाग में पीजी प्रीवियस में प्रवेश के लिए एक दिवसीय काउंसलिंग गुरुवार को हुई। काउंसलिंग के बाद भी सभी सीटें नहीं भरीं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स 75 फीसदी हाजिरी जरूरी होने के फार्म को देखकर वापस लौट गए। काउंसलिंग से बॉटनी की 20 और गणित की 40 सीटों पर प्रवेश दिया जाना था। बॉटनी में 33 और गणित में प्रवेश के लिए 30 विद्यार्थियों को बुलाया था। बॉटनी के लिए 20 विद्यार्थी ही पहुंचे। मैथ्स के लिए 22 विद्यार्थी आए। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पारीक के मुताबिक मैथ्स 7 सीटों पर वहीं बॉटनी में 11 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ है। दोनों विभागों में जो सीटें खाली रह गई हैं उन पर प्रवेश के लिए एक बार फिर एडमिशन पोर्टल खोला जाएगा।

गणित की भाषा हिंदी और सिंधी में भी समझ सकेंगे छात्र

जयपुर| अब गणित के कठिन शब्दों के बदले हिंदी के आसान शब्दों को ईजाद किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एसपीसीजीसीए के शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग शुरू की गई है। यह सब प्रक्रिया राजभाषा आयोग के निर्देश पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की देखरेख में किया जाएगा। गणित को मूलभूत शब्दावली योजना के तहत आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन यह प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 7 साल पहले राजनीति विज्ञान के लिए ऐसी ही शब्दावली ईजाद की गई थी। राजभाषा आयोग नई शब्दावली के आधार पर गणित की डिक्शनरी तैयार कराएगा। ताकि विद्यार्थियों के साथ ही आम लोग भी गणित की भाषा को आसान शब्दों में समझ सकें। इसके अलावा एसपीसी जीसीए के ही 6 शिक्षकों को सिंधी भाषा की शब्दावली गढ़ने के लिए चुना है। गुरुवार को पहली बैठक एसपीसी जीसीए में की गई।

महिला पर्यवेक्षक भर्ती : 60 पद बढ़ेंगे

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 22 जून को आयोजित की गई पर्यवेक्षक महिला (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) भर्ती में 60 पद बढ़ सकते हैं। इसके बाद इस भर्ती में पदों की संख्या 262 हो जाएगी। इससे पहले यह भर्ती 202 के लिए प्रारंभ की गई थी। पद बढ़ने का अधिकृत सूचना मिलने के बाद ही अब इस भर्ती का परिणाम जारी हो सकेगा। अभ्यर्थी इस भर्ती के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पद बढ़ने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए इस साल फरवरी-मार्च में आवेदन लिए गए थे। परीक्षा 22 जून को 7 शहरों में आयोजित की गई थी। इस भर्ती में 14977 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

भारतीय पशुपालन निगम : रिक्त पदों पर भर्ती करेगा

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा रिक्त चल रहे पदों को पुनः भरा जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग, कार्यालय सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रशिक्षण प्रभारी, प्रशिक्षण समन्वय प्रशिक्षण सहायक एवं पशु सेवक के शेष रहे 9173 पदों हेतु अगस्त एवं नवंबर में आवेदन मांगे जाएंगे।

अच्छी पहल • राजभाषा आयोग बना रहा डिक्शनरी, एसपीसीजीए में आई टीम, कमेटी का गठन

अब गणित की कठिन भाषा को भी आसान हिंदी और सिंधी में भी समझ सकेंगे विद्यार्थी

एजुकेशन रिपोर्टर | अजमेर

अब गणित के कठिन शब्दों के बदले हिंदी के आसान शब्दों को ईजाद किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एसपीसीजीसीए के शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग शुरू की गई है। ट्रेनिंग के लिए दिल्ली से एक टीम भी अजमेर पहुंच चुकी है। यह सब प्रक्रिया राजभाषा आयोग के निर्देश पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की देखरेख में किया जाएगा। गणित को मूलभूत शब्दावली योजना के तहत आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन यह प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 7 साल पहले राजनीति विज्ञान के लिए ऐसी ही शब्दावली ईजाद की गई थी। राजभाषा आयोग नई शब्दावली के आधार पर गणित की डिक्शनरी तैयार कराएगा। ताकि विद्यार्थियों के साथ ही आम लोग भी गणित की भाषा को आसान शब्दों में समझ सकें। इसके अलावा एसपीसी जीसीए के ही 6 शिक्षकों को सिंधी भाषा की शब्दावली गढ़ने के लिए चुना है। गुरुवार को पहली बैठक एसपीसी जीसीए में की गई।

एसपीसीजीसीए में गठित की गई टीम के सदस्य।

यह कमेटी गढ़ेगी नई शब्दावली

विजयराज सिंह शेखावत	योजना प्रभारी अधिकारी, सहायक निदेशक, सीएसटीटी दिल्ली
डॉ. चंद्र प्रकाश दादलानी	संयोजक, विभागाध्यक्ष, सिंधी विभाग एसपीसी जीसीए
डॉ. रवि प्रकाश टेकचंदानी	निदेशक, रासिमाविप नई दिल्ली
डॉ. हासो दादलानी	सदस्य एसपीसी जीसीए
डॉ. कैलाशचंद लक्ष्वानी	सदस्य एसपीसी जीसीए
डॉ. प्रिया आडवानी	सदस्य एसपीसी जीसीए
डॉ. जितेन्द्र थदानी	सदस्य एसपीसी जीसीए
डॉ. कमलराज पारदासानी	सदस्य एसपीसी जीसीए

ऐसा करने से यह होगा लाभ

एसपीसी जीसीए के प्राचार्य प्रोफेसर मनोज बहरवाल के मुताबिक एनईपी 2020 में कोर्सेज को आसान बनाने पर काम किया जा रहा है। हालांकि राजभाषा आयोग पहले से ही अलग अलग विषयों को आसान भाषा में समझाने के लिए शब्दावली तैयार करने मे जुटा है। इसका फायदा यह होगा कि विद्यार्थियों को यह विषय या इसमें शामिल कठिन फार्मूले, शब्द आसानी से समझ में आ सकेंगे। साथ ही विषय के बारे में गहनता से जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह भी मुमकिन है कि भविष्य में डिक्शनरी के अलावा इन शब्दों को बतौर रिफ्रेंस टेक्स्ट बुक में ही दे दिया जाए। बहरवाल ने बताया कि इसके लिए दिल्ली से टीम आई है। एक कमेटी का भी गठन किया गया है। टीम कमेटी को ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग 1 अगस्त से शुरू हो गई है जो 6 अगस्त तक चलेगी।

एमडीएसयू पीजी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का आयोजन, पूरी सीटें नहीं भरी

गणित की 40 सीटों पर 7 व बॉटनी की 20 सीटों पर 11 स्टूडेंट्स का एडमिशन

अजमेर| एमडीएस यूनिवर्सिटी के गणित और बॉटनी विभाग में पीजी प्रीवियस में प्रवेश के लिए एक दिवसीय काउंसलिंग गुरुवार को हुई। काउंसलिंग के बाद भी सभी सीटें नहीं भरीं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स 75 फीसदी हाजिरी जरूरी होने के फार्म को देखकर वापस लौट गए। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे चली काउंसलिंग के जरिये बॉटनी की 20 और गणित की 40 सीटों पर प्रवेश दिया जाना था। बॉटनी में 33 और गणित में प्रवेश के लिए 30 विद्यार्थियों को बुलाया था। बॉटनी के लिए 20 विद्यार्थी ही पहुंचे। मैथ्स के लिए 22 विद्यार्थी आए।

नियमित आने की सुन की कई विद्यार्थी वापस लौटे

काउंसलिंग में आए कई विद्यार्थियों को जब नियमित कक्षा में हाजिर होने संबंधित फार्म दिया गया तो विद्यार्थी चौंके।

विभागाध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि 75 प्रतिशत से हाजिरी कम हुई तो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए नियमित कक्षा में आना होगा। ऐसी बात सुनकर कई विद्यार्थी वापस लौट गए। फार्मेसी विभाग की काउंसलिंग शुक्रवार को होगी। इसमें डीफार्मा की 60 और बीफार्मा की 60 सीटों पर प्रवेश होना है।

विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पारीक के मुताबिक मैथ्स 7 सीटों पर वहीं बॉटनी में 11 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ है। दोनों विभागों में प्रवेश के बाद जो सीटें खाली रह गई हैं उन पर प्रवेश के लिए एक बार फिर एडमिशन पोर्टल खोला जाएगा।

इंजीनियरिंग कॉलेज बड़लिया

टीएफडब्ल्यूएस की कुल 19 सीटों पर 34 विद्यार्थी अलॉट

एजुकेशन रिपोर्टर | अजमेर

इंजीनियरिंग कॉलेजों में रीप 2024 के शेड्यूल के मुताबिक टीएफडब्ल्यूएस राउंड प्रथम के तहत बड़लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में 19 विद्यार्थी अलॉट किए गए थे। इनमें से 11 ने रिपोर्टिंग दी है। राउंड सैकंड के तहत 15 विद्यार्थियों और अलॉट किए गए हैं। कॉलेज में इस वर्ग की 19 सीटों के लिए कुल 34 विद्यार्थी अलॉट किए गए हैं।

बड़लिया इंजीनियरिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रेखा मेहरा ने बताया कि कॉलेज में 19 सीटों के लिए पहले 19 विद्यार्थी अलॉट किए थे। इनमें से 11 के प्रवेश हो चुके हैं। 8 सीट बची हैं। ऐसे में सैकंड राउंड में 15 विद्यार्थियों का अलॉटमेंट और किया गया है। इनमें से मेरिट के आधार पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर 8 सीटों पर प्रवेश होगा। इन 15 विद्यार्थियों को 5 अगस्त तक रिपोर्टिंग का समय दिया गया है।

दैनिक भास्कर

जोधपुर जिला 02-08-2024

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022

डमी अभ्यर्थी बैठा परीक्षा में सफल होने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया

जयपुर| एसओजी ने गुरुवार को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में स्वयं के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा में सफल होने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतियोगी परीक्षा में अरोपी की 76वीं रैंक आई थी। डीआईजी एसओजी परिस देशमुख ने बताया कि आरोपी अभिषेक विश्नोई 25 वर्ष निवासी खेतोलाई-जैसलमेर हाल वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमगुड़ा सिवाना बालोतरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने स्थान पर दोनों पारियों में दो अलग-अलग डमी अभ्यर्थियों से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 का पेपर दिलवाया था। अरोपी का परीक्षा केंद्र राजकीय सीनियर सैकंडरी स्कूल सुथारवाड़ा जैसलमेर आया था। उसकी प्रतियोगी परीक्षा में 76 वीं रैंक आई थी। आरोपी के बारे में शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच एसओजी की जोधपुर यूनिट के एडिशनल एसपी किशोर सिंह चौहान को सौंपी गई। इसके बाद हैड कांस्टेबल आशादीप व कांस्टेबल धर्मेंद्र ने आरोपी को जैसलमेर से गिरफ्तार किया। आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। अब उसके स्थान पर बैठने वाले डमी अभ्यर्थी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

'सीटेट' में 2.39 लाख अभ्यर्थी क्वालीफाई

अजमेर। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 19वीं केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.nic.in व www.ctet.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा में 3,66,279 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं। इनमें प्रथम पेपर में 1,27,159 व द्वितीय पेपर में 2,39,120 उम्मीदवार शामिल हैं। मालूम हो कि इस परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई को देशभर में किया गया था। सीटेट डायरेक्टर के अनुसार परीक्षा के लिए 25,30,065 उम्मीदवार पंजीकृत हुए थे। इसमें प्रथम पेपर में 8,30,242 व द्वितीय पेपर में 16,99,823 उम्मीदवार शामिल थे। कुल 20,86,039 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। सफल उम्मीदवारों को जल्द ही डिजिटल लॉकर के माध्यम से अंकतालिका और प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।

मालूम हो कि पहले पेपर की परीक्षा में कक्षा एक से पांचवीं यानि प्राथमिक स्तर के शिक्षक की पात्रता तथा दूसरे पेपर में छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षक की पात्रता के लिए परीक्षा हुई थी।

उत्तर मध्य रेलवे

No. Dy. CE/C/AGC/TN/2024/12
Dated: 31/07/2024

प्रथम शुद्धिपत्र

No. Dy CE/C/AGC/TN/2024/12 Dated: 11/07/2024
उपरोक्त निविदा सूचना में निम्नलिखित संशोधन किया गया है

Field Name	Existing Value	Modified Value
Advertised Value (₹)	₹1174012582.43	₹1151735461.99
Earnest Money (₹)	₹6020100.00	₹5908700.00
Tender Document	Tender document	Updated tender document

1214/24(DG)

DNA 325342

दैनिक भास्कर

अजमेर 02-08-2024

आरपीएससी मेंबर को एसीबी की क्लीन चिट से गड़बड़ी नहीं छुपेगी

अभ्यर्थियों ने की ईओ भर्ती जांच की मांग

एजुकेशन रिपोर्टर | अजमेर

आरपीएससी की विवादित परीक्षाओं में शामिल ईओ/आरओ भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों ने फिर से जांच कराने की बात कही है। यह 14 मई 2023 को कराई थी। इसमें भारी गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए थे। आयोग की दो महिला सदस्यों को भी एसीबी ने जांच के घेरे में लिया था। कुछ दिन पहले ही इन दोनों सदस्यों को क्लिन चिट मिल गई थी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि आयोग सदस्यों को क्लीन चिट मिलने से परीक्षा में गड़बड़ियों को नहीं छुपाया जा सकता है। जबकि इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। इस परीक्षा के अभ्यर्थी रहे पंकज कुमार का आरोप है कि मामले में एसीबी ने आयोग सदस्यों को क्लीन चिट दी है। लेकिन जो गड़बड़ियां और धांधली हुई थी वह अपनी जगह है। ऐसे में इसकी जांच एसओजी से कराई जानी चाहिए। पंकज का कहना था कि इस परीक्षा में पेपर लीक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकल, ओएमआरशीट में बदलाव जैसे आरोप लगे थे। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पंकज के मुताबिक इस परीक्षा में करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि परीक्षा देने वालों की तादाद लगभग एक लाख तक थी।

पंकज कुमार।